

बाजार	संसेक्स ↓	निफ्टी ↓
बंद हुआ	85,041.45	26,042.30
गिरावट	367.25	99.80
प्रतिशत में	0.43	0.38

सोना 1,42,300 प्रति 10 ग्राम  
चांदी 2,36,350 प्रति किलो

# अमृत विचार

हल्द्वानी, शनिवार, 27 दिसंबर 2025

www.amritvichar.com

# कारोबार

## बिजनेस ब्रीफ

### टाइटन मुंबई में खोलेंगी प्रयोगशाला में बने हीरों का पहला स्टोर

मुंबई। लाइफस्टाइल उत्पाद बनाने वाली कंपनी टाइटन ने प्रयोगशाला में बने हीरों का अपना पहला स्टोर मुंबई में खोलने की घोषणा की है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को बताया कि वह बीयोन प्रॉमि दि हाउस ऑफ टाइटन के ब्रांड नाम से 29 दिसंबर को मुंबई में अपना पहला स्टोर शुरू करेगी। यह चंडीयों, परफ्यूम, साड़ी और हैंगबैस से परे महिलाओं की लाइफस्टाइल जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। बीयोन प्रयोगशाला में बने हीरों के गहनों का स्टोर होगा। कंपनी की योजना निकट भविष्य में मुंबई और दिल्ली में कुछ और स्टोर खोलने की है।

### एलआईसी ने ग्रामीण भारत में पहुंच के लिए सहज से मिलाया हाथ

नई दिल्ली। सांख्यिक क्षेत्र की जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बीमा पहुंच को मजबूत करने के लिए सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। इसके तहत कानोराया फूड डेवेलपमेंट की सहज का सहायक डिजिटल सेवा नेटवर्क एलआईसी के जीवन बीमा उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाएगा। इस रणनीतिक सहयोग से लोगों को पॉलिसियों के बारे में समझने, पॉलिसी लेने और उसके प्रबंधन में मदद मिलेगी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बीमा के प्रति जागरूकता पारंपरिक रूप से कम रही है।

## हल्द्वानी मंडी

चावल: शरबी- 3300, मसूरी- 950, बासमती- 5400, परमल- 1100  
दाल दलहन : काला चना- 2700, साबुत चना दाल- 2400, मूंग साबुत- 4100, राजमा- 8400-12100, दाल उड़द- 6000, साबुत मसूर दाल- 3200, मसूर दाल- 3000, उड़द- 5300, ककली चना- 8000, अरहर दाल- 10000, लोबिया/करमानी- 1400

# वैश्विक प्रतिबंधों के दबाव में अग्रबत्ती में कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक

## लोगों के स्वास्थ्य और घरों के अंदर वायु गुणवत्ता को लेकर किया गया फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी

विश्व में अग्रबत्ती का सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक भारत ने उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया गुणवत्ता मानक निर्धारित किया है जिसके तहत अग्रबत्ती निर्माण में कुछ कीटनाशक रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कदम से करीब 8,000 करोड़ रुपये के अग्रबत्ती बाजार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इसके तहत उपभोक्ता सुरक्षा, घर के अंदर वायु गुणवत्ता, पर्यावरणीय स्थिरता और नियामकीय अनुपालन पर बढ़ते जोर के मद्देनजर अग्रबत्तियों के लिए एक अलग से भारतीय मानक 'आईएस 19412:2025' विकसित किया गया है। यह मानक कुछ सुगंधित यौगिकों और रसायनों पर वैश्विक स्तर पर लागू गए



### इन रसायनों का प्रयोग किया गया है निषिद्ध

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अग्रबत्ती में उपयोग के लिए निषिद्ध पदार्थों की एक सूची भी तय की है। सूची में एलेथिन, पर्मेथिन, साइपरमेथिन, डेटामेथिन और फिप्रोनिनल जैसे कुछ कीटनाशक रसायन शामिल हैं। इसके अलावा बैजिल सायनाइड, एथिल एफ्लिनेट और डाइफिनाइल एमीन जैसे कुत्रिम सुगंध मध्यवर्ती रसायनों पर भी रोक लगाई गई है। मंत्रालय के अनुसार, इन पदार्थों में से कई मानव स्वास्थ्य, घर के अंदर वायु गुणवत्ता और पर्यावरणीय सुरक्षा पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हैं।

प्रतिबंधों को भी ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, नए मानक का अनुपालन करने वाले उत्पाद बीआईएस मानक चिन्ह भी ले सकते हैं, जिससे

उपभोक्ताओं को आत्मविश्वास के साथ सूचित विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।

मंत्रालय ने कहा, इससे उपभोक्ता विश्वास बढ़ेगा, नैतिक और टिकाऊ विनिर्माण पद्धतियों

## आंध्र में वेदांता को 20 तटीय तेल और गैस कुएं खोदने को एनओसी

अमरावती, एजेंसी

आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा जिले में 20 तटीय तेल और गैस कुएं खोदने के लिए वेदांता लिमिटेड (केयन ऑयल एंड गैस डिवीजन) को शर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया है। आदेश के अनुसार यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल सिंचाई के दृष्टिकोण से जारी किया गया है और पूरी तरह अस्थायी प्रकृति का है। आवेदक को काम शुरू करने से पहले संबंधित विभागों से सभी आवश्यक अनुमतिपत्रों निर्धारित मानकों के अनुसार प्राप्त करनी होगी।

हालिया सरकारी आदेश के अनुसार वेदांता लिमिटेड ने एक आवेदन देकर कहा था कि उसकी कंपनी को खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति, 2018 के तहत तटीय

### ● कृष्णा जिले में खोदे जाएंगे तेल और गैस के कुएं, सरकार ने दी शर्त अनापत्ति

तेल और गैस क्षेत्र के विकास का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, कंपनी ने 35 स्थानों पर तटीय तेल और गैस के विकास और उत्पादन के लिए कुएं खोदने के लिए आंध्र प्रदेश के जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का अनुरोध किया था, क्योंकि प्रस्तावित ब्लॉक के बीच से बंदर नहर गुजरती है। आदेश में कहा गया, मामले की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, सरकार की ओर से शर्तों के अधीन मुंबई स्थित वेदांता लिमिटेड (केयन ऑयल एंड गैस डिवीजन) को 20 कुएं खोदने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

## छोटे उद्योगों पर बकाया कर्ज 46 लाख करोड़ रुपये हुआ

नई दिल्ली। छोटे उद्योगों पर बकाया कुल कर्ज बढ़कर 46 लाख करोड़ रुपये हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 सितंबर तक इसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सीआरआईएफ हाई मार्क - सिडबी की रिपोर्ट में कहा गया कि सक्रिय ऋण खातों की संख्या 11.8 प्रतिशत बढ़कर 7.3 करोड़ हो गई है।

नीतिगत समर्थन और एमएसएमई (छोटे एवं मझोले उद्यम) के लिए सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं ने इस गति को बनाए रखने में मदद की है। रिपोर्ट में कहा गया कि विभिन्न श्रेणियों में पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ऐसे में 91 से 180 दिनों तक की देरी वाले ऋण सितंबर 2025 तक घटकर लगभग 1.4 प्रतिशत रह गए, जो सितंबर 2023 में 1.7 प्रतिशत थे। उद्यमों का जोखिम प्रोफाइल लगातार कम बना हुआ है। एकल स्वामित्व वाले कारोबारों में भी स्थिर सुधार देखा गया है और सितंबर 2023 से सितंबर 2025 के बीच बहुत कम और कम जोखिम वाले उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी बढ़ी है।

संसेक्स में 367 अंकों की गिरावट, निफ्टी 100 अंक फिसला



मुंबई। विदेशी पूंजी की निकासी और घरेलू स्तर पर कोई बड़ा सकारात्मक संकेत न होने के कारण शुक्रवार को स्थानीय मानक बीएसई संसेक्स 367 अंक गिरकर बंद हुआ जबकि निफ्टी 100 अंकों के नुकसान में रहा।

बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक संसेक्स 367.25 अंक यानी 0.43 प्रतिशत गिरकर 85,041.45 अंक पर बंद हुआ जो इसकी गिरावट का लगातार तीसरा सत्र रहा। कमजोर कारोबार के बीच एक समय यह 470.88 अंक टूटकर 84,937.82 के स्तर तक आ गया था। एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी 99.80 अंक यानी 0.38 प्रतिशत गिरकर 26,042.30 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी लगातार दूसरे दिन नुकसान के साथ बंद हुआ। संसेक्स

## चांदी की चमक और तेज, 2.36 लाख रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर

नई दिल्ली, एजेंसी

मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में चांदी का भाव शुक्रवार को 9,350 रुपये बढ़कर 2,36,350 रुपये किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सराफा संघ के मुताबिक बुधवार को भाव 2,27,000 रुपये किलो रहा था। पिछले चार कारोबारी सत्रों में इसमें 32,250 रुपये यानी 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस साल चांदी की कीमत 31 दिसंबर, 2024 को 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम रही थी और तब से इसमें 1,46,650 रुपये यानी 163.5 प्रतिशत की तेजी आई है। इस बीच, सोने की कीमतों ने स्थानीय सराफा बाजार में तेजी बरकरार रखी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,500 रुपये बढ़कर सभी करों सहित 1,42,300 रुपये 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यह पिछले कारोबारी सत्र में 1,40,800 रुपये पर बंद हुई थी। इस साल अब तक, सोने का भाव 31 दिसंबर, 2024 को दर्ज 78,950 रुपये 10 ग्राम से 63,350 रुपये यानी 80.24 प्रतिशत बढ़ा है।



### ● पिछले चार कारोबारी सत्रों में हुई 32,250 रुपये की भारी वृद्धि

## विदेशी मुद्रा भंडार 4.37 अरब डॉलर बढ़ा, स्वर्ण भंडार रिकॉर्ड स्तर पर

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 4.368 अरब डॉलर बढ़कर दो महीने के उच्चतम स्तर 693.318 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह लगातार तीसरा सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। इससे पहले 12 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में इसमें 1.689 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी और यह 688.949 अरब डॉलर पर रहा था। रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का दूसरा सबसे बड़ा घटक स्वर्ण भंडार 2.623 अरब डॉलर बढ़कर 110.365 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर रहा। आलोच्य सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 1.641 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 559.428 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

## नीदरलैंड के लोगों ने टाटा स्टील से मांगा 1.4 अरब यूरो का हर्जाना

मुंबई, एजेंसी

नीदरलैंड के वेल्सन-नूरड के निवासियों ने टाटा स्टील पर स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए 1.4 अरब यूरो (लगभग 148 अरब रुपये) के हर्जाने की मांग के लिए मुकदमा दायर किया है। नेल्सन-नूरड के निवासियों के संगठन स्ट्रिचिंग फ्रिस विंड.एनयू (एसएफडब्ल्यू) ने हारलेम स्थित उत्तरी हॉलैंड की जिला अदालत में यह केस दायर किया है। अदालत की ओर से मामले में टाटा स्टील नीदरलैंड बीवी और टाटा स्टील

### ● कंपनी के संयंत्रों के कारण स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने का लगाया आरोप

इज्जुदेन को समन जारी किए गए हैं। टाटा स्टील ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। आरोप है कि कंपनी के संयंत्रों के कारण स्थानीय निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ गये हैं। टाटा स्टील ने कहा है कि एसएफडब्ल्यू ने आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे उसके दावों में तथ्यों की कमी है और ये सिर्फ कल्पना पर आधारित हैं। याचिका सार्वजनिक दावों के सामूहिक निपटान संबंधी

डच कानून (डब्ल्यूएएमसीए) के तहत दायर की गई है।

कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया है कि इसके तहत दो चरणों में सुनवाई पूरी होती है। पहला चरण मामलों की स्वीकार्यता का होता है और दूसरे चरण में उसके गुण-दोष पर विचार किया जाता है। दोनों चरणों में अलग-अलग दो-तीन साल का समय लगता है। इसलिए, आने वाले समय में (पहले चरण के दौरान) हर्जाने की राशि पर अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। टाटा स्टील ने कहा है कि वह एसएफडब्ल्यू द्वारा मुहैया कराए गए दस्तावेजों का अध्ययन कर रही है।

## राष्ट्रीय

# दुष्कर्म के दोषी सेंगर की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पर प्रदर्शन

## उज्जाव बलात्कार मामला: जमानत रद्द करने की मांग करते हुए की जमकर नारेबाजी

नई दिल्ली, एजेंसी

उज्जाव बलात्कार मामले के दोषी तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उधेकंद की सजा निलंबित करने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को यहां दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एआईडीडब्ल्यूए) के बैनर तले हुए इस विरोध प्रदर्शन में संगठन की कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और पीड़िता की मां ने भी हिस्सा लिया और सेंगर को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की। इस दौरान दुष्कर्म पीड़िता की मां ने कहा कि वह सेंगर की सजा को निलंबित करने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगी।

पीड़िता की मां ने कहा कि वह अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ हाईकोर्ट के बाहर विरोध जताने आई हैं। उन्होंने कहा, मैं पूरे उच्च न्यायालय को दोष नहीं देती, लेकिन दो न्यायाधीशों के फैसले से हमारा भरोसा टूट गया है और मुझे गहरा आघात पहुंचा है। पहले न्यायाधीशों ने उनके परिवार को



दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर इकट्ठे प्रदर्शनकारी और मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स।

न्याय दिलाया था, लेकिन अब आरोपी को जमानत दे दी गई है। पीड़िता की मां ने कहा, यह हमारे परिवार के साथ अन्याय है। हम उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। हाईकोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर लिखा था, 'कुलदीप सेंगर की उधेकंद की सजा बरकरार रहे' और 'महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा।' उन्होंने 'बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो' और 'गुनहगारों को बचाना बंद करो' जैसे नारे भी लगाए। इस

फैसले को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा, भाजपा सरकार या अदालत उन्हें जमानत कैसे दे सकती है, उन्हें उनकी जमानत याचिका खारिज करनी होगी, नहीं तो इस सरकार को सत्ता से बाहर जाना होगा। एक महिला ने कहा, यह कोई संयोग नहीं है कि अदालती छुट्टियों से ठीक दो दिन पहले जमानत दी गई। यह एक सोचिसमझी चाल है। इस देश के नागरिक मूर्ख नहीं हैं। कब तक वे हमें धोखा देते रहेंगे। सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए एक अन्य

### ● पीड़िता की मां ने की मां का शीर्ष अदालत जाने की घोषणा

प्रदर्शनकारी ने कहा, उसने एक लड़की का बलात्कार किया और उसके पिता की हत्या कर दी, जिसके कारण वह (पीड़िता) अब भी इस हालत में है। बलात्कारी को संरक्षण देना बंद करो और पीड़ितों की रक्षा करो। जब मना करने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने विरोध जारी रखा तब दिल्ली पुलिस ने लाउडहेलर के जरिए घोषणा की कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पुलिस ने उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। कहा, यहां प्रदर्शन करना प्रतिबंधित और गैरकानूनी है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो जंतर-मंतर जाएं।

## पश्चिम बंगाल: होटलों में बांग्लादेशी नागरिकों के ठहरने पर रोक

कोलकाता, एजेंसी

पश्चिम बंगाल के होटल मालिकों के एक संगठन ने पड़ोसी बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिर-पृथल के मद्देनजर सिलीगुड़ी और उसके आसपास के इलाकों में बांग्लादेशी नागरिकों को ठहरने की सुविधा देने पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला किया है। मालदा सहित कई और शहरों में ऐसा ही प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। 'ग्रेटर सिलीगुड़ी होटलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन' की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, यह निर्णय उन घटनाओं से जुड़ा है, जिनसे भारत-

### ● पड़ोसी देश में भारतविरोधी गतिविधियों को लेकर सिलीगुड़ी के होटल मालिकों का फैसला कई और शहरों में ऐसे ही प्रतिबंध की तैयारी

बांग्लादेश संबंधों में तनाव आया है, जिसमें भारतीय ध्वज के प्रति अनादर और बांग्लादेशी नागरिकों के एक वर्ग के भड़काऊ बयान शामिल हैं। होटल संगठन ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य वर्तमान संवेदनशील माहौल में मेहमानों और होटल कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना है। संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया कि एसोसिएशन के सदस्य अगले आदेश तक

बांग्लादेशी नागरिकों को होटल में 'चेक-इन' की अनुमति नहीं देंगे।

उत्तर बंगाल में अंतरराष्ट्रीय सीमा और मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाले रणनीतिक रूप से संवेदनशील गलियारों के पास स्थित सिलीगुड़ी, पर्यटक, चिकित्सा और छात्र वीजा पर भारत आने वाले बांग्लादेशी आगंतुकों के लिए एक प्रमुख प्रवेश बिंदु रहा है। एसोसिएशन ने कहा कि इस प्रतिबंध की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और स्थितियों सुरक्षित तथा सम्मानजनक होने पर उद्देश्यों की सुविधाओं को फिर बहाल करने की संभावना पर विचार किया जाएगा।

मध्यस्थता कानून के बेहद विकसित होने का संकेत: सीजेआई

पणजी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मध्यस्थता कानून के कमजोर होने का नहीं बल्कि बेहद विकसित होने का संकेत है। सीजेआई दक्षिण गोवा के सांकोले गांव में शुक्रवार को भारतीय अंतरराष्ट्रीय विधि शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सम्मेलन 'मध्यस्थता: वर्तमान संदर्भ में इसका महत्व' को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा, मध्यस्थता न्यायिक निष्पत्ति से सहभागिता की संस्कृति को अग्र बढ़ाना है, जहां हम सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे न्यायालय की कल्पना करते हैं जहां न्यायालय केवल मुकदमे की सुनवाई का स्थान न हो बल्कि विवाद समाधान का एक व्यापक केंद्र हो। इससे पहले दिन में सीजेआई ने पणजी में कला अकादमी के पास 'मध्यस्थता जागरूकता' के लिए एक प्रतीकात्मक पदयात्रा में भाग लिया।

## बच्चों के इंटरनेट उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए केंद्र सरकार

मद्रुरै, एजेंसी

मद्रास हाईकोर्ट की मद्रुरै पीठ ने व्यवस्था दी है कि केंद्र सरकार बच्चों के इंटरनेट का उपयोग किए जाने को विनियमित करने के लिए उसी तरह एक कानून बनाने पर विचार कर सकती है, जैसा कानून ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। अदालत ने कहा कि जब तक ऐसा कोई कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों में बाल अधिकारों और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर सकता है। अदालत की ओर से सुझाए गए ढांचे का उद्देश्य 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने से रोकना है, क्योंकि नाबालिगों के हानिकारक ऑनलाइन सामग्री के संपर्क में आने की आशंका है। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और न्यायमूर्ति केके रामकृष्णन की

## लखनऊ-अयोध्या समेत 48 स्टेशनों को भीड़भाड़ से मुक्त कराने की योजना

### पांच साल में बढ़ेगी अतिरिक्त प्लेटफॉर्म समेत कई सुविधाएं

नई दिल्ली, एजेंसी

रेलवे ने व्यस्त स्टेशनों को भीड़भाड़ से मुक्त करने और यात्री सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 2030 तक 48 प्रमुख शहरों में ट्रेनों की शुरुआती क्षमता को लगभग दोगुना करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में इन स्टेशनों पर क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा ताकि आने वाले वर्षों में यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिले।

यह योजना कार्यों को तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक समेत तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शॉटिंग सुविधाओं के साथ बढ़ाया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्र और उसके आसपास

### इन शहरों के स्टेशन शामिल होंगे योजना में

इस योजना में शामिल स्टेशनों में दिल्ली, जम्मू, मुंबई (मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे), जोधपुर, कोलकाता (पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, कोलकाता मेट्रो), जयपुर, चेन्नई, वडोदरा, हैदराबाद, सूरत, बेंगलुरु, मडगांव, अहमदाबाद, कोचीन, पटना, पुरी, लखनऊ (उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे), भुवनेश्वर, पुणे, विशाखापटनम, नागपुर (मध्य रेलवे, एसईसीआर), विजयवाड़ा, वाराणसी (उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे), तिरुपति, कानपुर, हरिद्वार, गोरखपुर, गुवाहाटी, मथुरा, भागलपुर, अयोध्या, मुजफ्फरपुर, आगरा, दरभंगा, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया, चंडीगढ़, मैसूर, लुधियाना, कोयंबटूर, अमृतसर, टाटानगर, इंदौर, रांची, भोपाल, रायपुर, उज्जैन और बरेली हैं।

नए टर्मिनलों की पहचान करना और बनाना, रखरखाव सुविधाएं, जिसमें मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स शामिल हैं और यात्री सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग अपग्रेडेशन और विभिन्न बिंदुओं पर बढ़ी हुई ट्रेनों को संभालने के लिए आवश्यक मल्टीट्रैकिंग के साथ लाइन क्षमता बढ़ाना भी शामिल होगा।

स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने की योजना बनाते समय उसके आसपास के स्टेशनों पर भी विचार किया

जाएगा ताकि क्षमता समान रूप से संतुलित हो। उपरोक्त अभ्यास उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों तरह के ट्रेफिक के लिए किया जाएगा, जिसमें दोनों सेगमेंट की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। इस योजना में ट्रेनों को संभालने की क्षमता को समय पर दोगुना करने के लक्ष्य को पाने के लिए प्लान किए गए, प्रस्तावित या पहले से मंजूर काम शामिल होंगे।

## दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल, एयर प्यूरीफायर पर क्यों नहीं घटा सकते जीएसटी

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए आम आदमी के लिए एयर प्यूरीफायर को किफायती बनाने के लिए उस पर लगने वाले जीएसटी को क्यों नहीं घटाया जा सकता। हाईकोर्ट ने केंद्र के समक्ष यह प्रश्न तब उठाया जब केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने यह तर्क दिया कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है और यह अब दिल्ली का एक्टरफा कर नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह पूरे भारत में लागू संघीय कर है, इसलिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहमति आवश्यक है और इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने कहा कि मतदान प्रत्यक्ष तौर पर होना है और यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस मामले में एक अत्यंत विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करेगी।